



www.agrabharat.in

वर्ष: 19

अंक: 106

आगरा, रविवार 04 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रू.

नीट यूजी, यूपीएससी सीएसई, जेईई मेन जैसी परीक्षाएं दुनिया की बड़ी परीक्षाओं में शामिल

नई दिल्ली,(ए)। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रेनें भर जाती हैं, होटलों में कमरे नहीं मिलते और अभ्यर्थियों के साथ माता-पिता भी परेशान होते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया रिसर्च की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो इन आंकड़ों पर मुहर लगाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूजी, यूपीएससी सीएसई, जेईई मेन और यूजीसी नेट जैसी भारत की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल हैं। यह रिपोर्ट देश में शिक्षा और सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं के जुनून का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त है। इस ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट में चीन की ‘गोआकोआ’ पहली रैंक पर है, जिसमें करीब 1.29 करोड़ छात्र बैठते हैं। वहीं, भारत की नीट यूजी परीक्षा करीब 25 लाख आवेदनों के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके अलावा, यूपीएससी सीएसई में 12 लाख, जेईई मेन में 10 लाख और यूजीसी नेट में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हर साल हिस्सा लेते हैं।

एसबीआई की यह रिपोर्ट सिर्फ



आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह भारतीय परीक्षा प्रणाली की ताकत और उसकी कमजोरियों को भी बेनकाब करती है। इतने बड़े पैमाने पर युवा अपने भविष्य के लिए इम्तिहान दे रहे हैं, ऐसे में यह सोचना जरूरी हो जाता

है कि क्या हमारी व्यवस्था इन परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को बचा पा रही है? रिपोर्ट में भारत की 4 प्रमुख परीक्षाओं को खास जगह मिली है। इनमें मेडिकल के लिए नीट-यूजी, सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी सीएसई,

इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन और हायर एजुकेशन-रिसर्च के लिए यूजीसी नेट शामिल हैं। चीन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जो इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं का आयोजन करता हो। हमारे यहां परीक्षा

का आयोजन किसी राष्ट्रीय उत्सव या मेगा इवेंट जैसा होता है, जिसमें देश की पूरी प्रशासनिक मशीनी झोंक दी जाती है।

इस रिसर्च का सबसे अहम पहलू यह है कि यह सिर्फ कमियां गिनाकर चुप नहीं बैठती, बल्कि चीन और अन्य देशों के बेहतर तौर-तरीकों से सीखने की सलाह देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को एक ऐसा मजबूत ‘नेशनल टेस्टिंग फ्रेमवर्क’ चाहिए जो डिजिटल मार्किंग, इमरजेंसी रिजर्व सेंटर और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक पारदर्शी सिस्टम से लैस हो। देश के करोड़ों युवा अपनी मेहनत के दम पर भविष्य सवारने निकलते हैं, तो सिस्टम की यह जिम्मेदारी है कि उनकी उम्मीदों पर कोई आच न आए और उन्हें एक निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा का माहौल मिले। यह तय करना अत्यंत जरूरी है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें उचित तरीके से मिले और किसी भी प्रकार की धांधली उनके भविष्य को अंधकारमय न करे।

दीपके के खिलाफ थाने पहुंची ऐडवोकेट, दर्ज करवाई शिकायत

मुंबई(ए)। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क के बाहर शुक्रवार को काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां सीजेपी के प्रवक्ताओं (जिनमें अभिजीत दीपके भी शामिल हैं) ने सरकार पर तीखा हमला बोला। इस प्रदर्शन को लेकर स्थानीय स्तर पर तीखा विरोध देखने को मिला। शिवाजी पार्क के आसपास रहने वाले निवासी शुरुआत से ही इसके खिलाफ थे। प्रदर्शन के बाद, वकील सिद्धी देवलेकर ने अभिजीत दीपके और सीजेपी के संस्थापकों के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि पुलिस से अनुमति न मिलने के बावजूद यह प्रदर्शन किया गया, जिससे इलाके की शांति भंग करने का प्रयास किया गया। वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2013 के उस फैसले का हवाला दिया, जिसके तहत शिवाजी पार्क में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। इसी आदेश का पालन करते हुए मुंबई पुलिस ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर भारी भीड़ जुटाई गई, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस आयोजन के विरोध में कई जगहों पर स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते यह पूरा मामला राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गया है।

पुलिस जहां रोकेगी वहीं धरना शुरु कर देगी सीजेपी

मुंबई(ए)। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपने आंदोलन की रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन के बाद संगठन ने देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करने की अपनी पूर्व योजना को स्थगित कर सीधे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। सीजेपी ने घोषणा की है कि 10 अक्टूबर को वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर कथित प्रतिबंध की आशंका को देखते हुए, सीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई है- उन्हें जहां भी रोका जाएगा, उसी स्थान को जंतर-मंतर में बदल दिया जाएगा।

शुरुआत में, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों की बात कही थी, जिसके तहत दिल्ली पहुंचने से पहले विभिन्न शहरों में आंदोलन चलाए जाने थे। हालांकि, मुंबई में शिवाजी पार्क के प्रदर्शन के तुरंत बाद, दीपके ने 10 अक्टूबर को सीधे जंतर-मंतर पर जुटने की घोषणा कर दी। बाद में सीजेपी के नेशनल वर्किंग कमेटी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने बताया कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। हालांकि, संगठन ने इस तत्काल बदलाव के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है। दीपके ने घोषणा करते हुए कहा, यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो देशभर के काँकरोच 10 अक्टूबर को दिल्ली आएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि यह आंदोलन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित होगा और सरकार तथा दिल्ली पुलिस पर निर्भर करेगा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करें या पिछली घटनाओं की तरह बर्बरता दोहराएं।

सीजेपी इस बात से अवगत है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद से पुलिस जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। हाल ही में मुस्लिम संगठनों और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, दीपके ने कहा, यदि दिल्ली पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, तो वे हमें जहां रोकेंगे, वही हमारा जंतर-मंतर बन जाएगा। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने इस अवधारणा को विस्तार से समझाया, उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर असहमति का प्रतीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे इस तरह बंद कर दिया है जैसे वहां कोई बड़ा खजाना छिपा हो। दास के अनुसार, आज जंतर-मंतर उम्मीद, साहस, लोगों के टूटे हुए सपने और जीत का प्रतीक है। इसलिए, जहां भी लोग जुटेंगे और उन्हें रोका जाएगा, वही स्थान जंतर-मंतर कहलाएगा। जिस भी स्थान पर लोग जवाबदेही मांगेंगे, वह जंतर-मंतर कहलाएगा। आशुतोष रांका ने इस आंदोलन को देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि एक समझौता कर चुका चुनाव आयोग लोकतंत्र की नष्ट करने की ओर है। उन्होंने लाखों भारतीयों के लिए न्याय की मांग की, जिन्हें ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट से हटा दिया है। सीजेपी का लक्ष्य है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में शांतिपूर्वक एकत्रित होकर लोकतंत्र को वापस पाया जाए।

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

डीजल संकट से दो-चार हुई दुनिया, अमेरिका से भारत तक ईंधन आपूर्ति पर बढ़ा दबाव

नई दिल्ली,(ए)। दुनिया इस समय कच्चे तेल की उपलब्धता से ज्यादा डीजल और अन्य रिफाईंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर दबाव में है। अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और भारत समेत कई देशों में डीजल की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा संकट के पीछे केवल कच्चे तेल की कमी नहीं, बल्कि युद्ध, रिफाइनरियों पर हमले, आपूर्ति मार्गों में बाधा, रिफाईनिंग क्षमता में कमी और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण जैसे कई कारण हैं।अमेरिका में हालात इस कदर दबावपूर्ण हुए कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की संभावना तक पर विचार किया गया। अमेरिका ने यूरोपीय देशों से अपने रणनीतिक डीजल भंडार को बाजार में उतारने का आग्रह भी किया है। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया के प्रमुख ऊर्जा बाजारों में शामिल अमेरिका भी आपूर्ति संबंधी दबाव से अछूता नहीं है। यूरोप की चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि वह अमेरिकी डीजल आपूर्ति पर निर्भर है। दूसरी ओर, रूस ने अक्टूबर के अंत तक डीजल निर्यात प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यूक्रेन की ओर से रूसी तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचे पर किए गए हमलों से वहां की रिफाईनिंग क्षमता और निर्यात प्रभावित होने की बात सामने आई है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय



बाजार में डीजल की कीमत करीब 1,500 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है, जो संकट से पहले के स्तर की तुलना में लगभग दोगुनी बताई जा रही है।

भारत के सामने दोहरी चुनौती

भारत के लिए मौजूदा स्थिति चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आई है। भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है, लेकिन उसकी बड़ी रिफाईनिंग क्षमता उसे वैश्विक पेट्रोलियम बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका देती है। पश्चिमी देशों में डीजल की कमी बढ़ने पर भारतीय रिफाइनरियों के लिए निर्यात की मांग बढ़ सकती है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि से भारत की आयात लागत बढ़ेगी, जिसका असर परिवहन, कृषि और घरेलू महंगाई पर पड़ सकता है।

डीजल संकट का असर केवल

पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं है। ट्रक, बस, निर्माण मशीनें, कृषि उपकरण, जनेरेटर और माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है। ईंधन महंगा होने पर खाद्यान्न से लेकर औद्योगिक कच्चे माल और रोजमर्रा की वस्तुओं तक की परिवहन लागत बढ़ सकती है। अमेरिका में किसानों के लिए फसल कटाई की लागत बढ़ने की स्थिति भी सामने आई है।

रणनीतिक भंडार से राहत की कोशिश

संकट के बीच जी-7 देशों ने 100 मिलियन बैरल कच्चे तेल और डीजल समेत पेट्रोलियम भंडार जारी करने पर सहमति जताई है। यूरोप भी अपने रणनीतिक भंडार से डीजल बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है।

तिरुपति फैक्ट्री में भीषण धमाका: 5 मजदूरों की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर

तिरुपति(ए)। जिले के सत्यवेडु विधानसभा क्षेत्र में स्थित श्री सिटी औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री

में बीते शनिवार को एक भीषण बॉयलर धमाके में पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए तिरुपति के आर्यूए और एसबीआईएमएस अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की छत की चारों

और मशीनें दूर तक जा गिरीं, जिसके बाद परिसर में भीषण आग लग गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया।

हादसे के वक्त फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। बॉयलर यूनिट से अचानक तेज आवाज आई और पलक झपकते ही जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। कुछ लोग झुलस गए जबकि

कई मलबे में दब गए, जिससे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए मजदूर



बदहवास होकर बाहर की तरफ भागे। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव दलों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को एंबुलेंस की मदद से फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। कई मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है,

उठने लगे हैं। मजदूर संगठनों ने आरोप लगाया है कि यूनिट में बुनियादी औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और बॉयलर का रखरखाव भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे की वास्तविक वजह का पता

जिस पर सवाल उठे वही संभाल रहा है ईसी की आईटी विंग

नई दिल्ली(ए)। भारतीय चुनाव आयोग के भीतर मंचे अंदरूनी घमासान और स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) विवाद में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की तरफ से कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमानाथ को लिखी गई गोपनीय चिट्ठियों में वरिष्ठ डिट्टी चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के एक अहम फैसले पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। यह फैसला आयोग के आईटी विभाग के स्तर को समाप्त करने से जुड़ा था, जिससे विवाद और गहरा गया। यह पूरा मामला चुनाव आयोग की डीजी (आईटी) डॉ. सीमा खन्ना के कामकाज और उनकी फाइलों को सीधे बड़े अधिकारियों तक भेजने के लिए रूटिंग प्रक्रिया में किए गए नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2026 में, चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव को एक जैसी भाषा में दो अलग-अलग पत्र भेजे थे। इन पत्रों में स्पष्ट किया गया था कि वरिष्ठ डिट्टी चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने एक आदेश जारी कर आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना की फाइलों की समीक्षा करने वाले डिट्टी चुनाव आयुक्त (डीईसी) संजय कुमार की भूमिका को बीच से हटा दिया था। चुनाव आयुक्तों ने तर्क दिया कि संजय कुमार एक वरिष्ठ और अनुभवी आईएसएस अधिकारी हैं, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की गहन समझ रखते हैं। उनका कहना था कि सीमा खन्ना की फाइलें सीधे मनीष गर्ग के जरिए भेजे जाने से आईटी विभाग की समीक्षा प्रणाली कमजोर हुई थी, जो चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से दी गई उस सफाई के पीछे भी यही संदर्भ था, जिसमें आयोग ने दावा किया था कि यह चिट्ठी किसी नीतिगत विवाद को लेकर नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ी थी। विवाद के तूल पकड़ने के बाद हालांकि दोनों चुनाव आयुक्तों के हस्तक्षेप से मनीष गर्ग के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था और निगरानी का स्तर बहाल रखा गया था। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। यूटी कैडर के आईएसएस अधिकारी संजय कुमार ने व्यक्तिगत कारणों से अगस्त में अपने मूल कैडर में वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संजय कुमार के जाने के बाद उनकी सभी जिम्मेदारियां और प्रभार खुद मनीष गर्ग के पास आ गए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि अब सीमा खन्ना की फाइलें वापस मनीष गर्ग के माध्यम से ही दोनों चुनाव आयुक्तों के पास पहुंच रही हैं, जिससे मूल चिंता फिर से उभर आई है। आईटी विभाग की फाइल रूटिंग का यह मुद्दा इसलिए बेहद संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है क्योंकि सीमा खन्ना और उनका आईटी विभाग ही ईसीनेट और एसआईआर विवाद के केंद्र में हैं। एक प्रमुख रिपोर्ट के अनुसार, सीमा खन्ना की ओर से तैयार किए गए और चुनाव आयोग से स्वीकृत नए आईटी सिस्टम/प्रोटोकॉल ने स्थानीय स्तर पर नाम जोड़ने और काटने वाले संवैधानिक अधिकारियों - इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ) और डिट्टी ईआरओ से ही डेटाबेस के एक्सेस छिन लिए थे।

